CHAPTER-V

AIACE IN MEDIA

धनबाद 09-10-2022

दैनिक भास्कर SUNDAY

संघ सीएमपीएफ कार्यालय के समक्ष कल देगा धरना

धनबाद| अखिल भारतीय कोयला पेंशनभोगी संघ (एआईसीपीए) के बैनरतले देश भर के सभी कोयला पेंशनभोगी 10 अक्टूबर को सीएमपीएफ के मुख्य कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सामने धरना देंगे। संघ के संयोजक पीके सिंह राठौर ने बताया कि पेंशनर्स की मुख्य मांगों में कोयला खान पेंशन योजना के पुनर्गठन के लिए लोक लेखा समिति की 12वीं रिपोर्ट में निहित सुझावों पर त्वरित कार्यान्वयन करने, सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद समान पेंशन सुनिश्चित करने के लिए पेंशन के हिस्से के रूप में महंगाई राहत (डीआर) घटक को शामिल करने, सभी सरकारी और निजी कोयला कंपनियों से हर 3 साल में सेस बढ़ाने के प्रावधानों के साथ 20 रुपए प्रतिटन के सेस के अनिवार्य संग्रह की प्रक्रिया को तेज करने, 3 साल में पेंशन की समीक्षा और संशोधन के लिए सीएमपीएस-1998 में अधिनियमित प्रावधानों का पालन करने, सरकारी नीति के अनुरूप पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने और बैंक स्तर पर विधवा, विधुर पेंशन शुरू करने की सरल प्रक्रिया को बार-बार शुरू करने की घोषणा करने के बजाय, प्रक्रिया को सही मायने में शुरू करना शामिल है।

सीआईएल के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के धरने का आयोजन

अखिल भारतीय कोयला पेंशनभोगी ने दिया धरना

फ्रीडम फाइटर संवाददाता

रजरप्पा : रांची स्थित कोयला खान भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष सीआईएल के सेवानिवृत एवम कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अखिल भारतीय कोयला पेंशनभोगी संघ (एआईसीपीए) के तत्वावधान में अपनी निम्नलिखित माँगों के लिए विशाल धरने का आयोजन संघ के महासचिव ए के सिंह के नेतृत्व में किया गया।

संघ की प्रमुख मांगें

1. कोयला खान पेंशन योजना के पुनर्गठन के लिए संसद की लोक लेखा समिति की १२वीं रिपोर्ट में निहित सुझावों पर त्वरित कार्यान्वयन

2. कोयला कर्मियों के पेंशन स्कीम में संशोधन एवम पेंशन को मंहगाई भत्ता में वृद्धि के अनुरूप बढ़ोतरी

3. पेंशन स्कीम की प्रत्येक तीन साल पर समीक्षा व संशोधन

4. सेवानिवृत कामगारों की मृत्यु के पश्चात विधवा/विधुर के पेंशन को शुरू करने की प्रक्रिया को सरल करना यानि उसे बैंक स्तर पर शुरू करना

5. सरकारी नीति के अनुरूप पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करना

6. सभी सरकारी और निजी कोयला कंपनियों से हर तीन साल में सेस बढ़ाने के प्रावधानों के साथ २० रुपए प्रति टन के सेस के अनिवार्य संग्रह की प्रक्रिया को तेज करना।

धरने में सीसीएल, ईसीएल, बीसीसीएल, एसईसीएल सीएमपीडीआई के कर्मियों के अलावा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में आए हुए कर्मी उपस्थित रहे।

दोपहर १२ बजे महासचिव ए के सिंह के नेतृत्व में ११ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सीएमपीएफओ रांची के रीजनल कमिश्नर से मिला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में संघ अध्यक्ष एम आई आलम, रत्नेश कुमार, एम एम हक, हरीश ठाकुर, एस एस राय, एच के सिन्हा, एस सी पोद्दार, एस एन मिश्रा, ओ पी नारायण और शांति प्रसाद मिश्रा शामिल थे। एक बजे संघ के अध्यक्ष एम आई आलम के धन्यवाद ज्ञापन के बाद धरना समाप्ति की घोषणा की गई।

Coal pensioners to stage pan-India protest

Demand Centre to revise Coal Mines Pension Scheme-1998

STATE BUREAU
Hyderabad

Coal pensioners across the country will stage a dharna on October 10 in front of the CMPF Office at Dhanbad in Jharkhand and all regional offices of the CMPF to press their demand for the review and revision by the Centre of pension under the Coal Mines Pension Scheme (CMPS), 1998.

According to K Singh Rathor, convenor of All India Coal Pensioners Association (AICPA), coal pensioners across the country would stage a dharna from 10 am to 1 pm on the day. A memorandum of demands would be submitted to the Commissioner of CMPF and Regional Commissioners after the dharna.

All India Coal Pensioners Association to stage a dharna from 10 am to 1 pm at all CMPF offices on October 10

Primary demands

Their main demands are the speedy implementation of suggestions contained in the 12th Report of Public Accounts Committee for Restructuring of Coal Mines Pension Scheme (presented in Parliament on 18th March, 2020); Incorporating Dearness Relief (DR) component as a part of the pension to ensure the equitable pension irrespective of retirement date; Hasten the process of compulsory collection of cess of Rs 20 per tonne, with provisions for enhancement of cess every three years, from all government and private coal companies; and abide by the provisions enacted in CMPS-1998 to review and revise pension every three years.

Minimum pension

The demands will also include ensuring minimum pension to the pensioner in line with government policy and the launch of a simplified process of starting widow/widower pension at the bank level.

Dharna sites

The dharna will be staged at Kothagudem, Ramagundam, Nagpur, Bilaspur, Talcher, Kolkata, Asansol, Ranchi, Dhanbad, Deoghar, Jabalpur, Chhindwara and other places, Rathor said in a press release.

Appeal to pensioners

Singareni Retired Employees Welfare Association, Hyderabad, president D Ramchander Rao requested coal pensioners across Telangana to participate in the demonstrations at the locations nearby. In the State, the protests would be held at Godavarikhani and Kothagudem where the CMPF offices (Coal Mines Provident Fund) are located. The idea is to pressure the Union Ministry of Coal for the enhancement of pension, he said.

कोल पेंशनरों ने सहायक कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

क्षेत्रीय आयुक्त कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय पर दिया धरना

दैनिक बंसी संदेश, बैतूल।

बैतूल। कोल माइंस पेंशनर एसोसिएशन एचएमएस के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार सहायक कमिश्नर को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष दिनकर साहू ने बताया कि सीएजी, पीएसी सुझावों पर सुस्त कार्रवाई और पेंशन पुनरीक्षण, वृद्धि ना होने के विरोध में एचएमएस के प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्रीय आयुक्त कोयला खान भविष्य निधि छिंदवाड़ा कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। इसके बाद सहायक कमिश्नर को छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आयुक्त धनबाद नई दिल्ली कोयला मंत्री के नाम सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष डीके साहू, महामंत्री दयाराम झरबडे, उपाध्याय अजय सिंह राजपूत, मानिकराव कापसे कोषाध्यक्ष नागौराव वागद्रे, मुलताई शाखा से अध्यक्ष बीआर गवाड़े, सचिव उमराव, महासचिव अशोक सेलकरी, नारायण मिश्रा, विजय वर्मा, रामदास पंडाग्रे, इंदल पारधे, रामाशंकर, बाजीराव इंगवे, कुंदन लाल चौधरी, प्रेम लाल पंवार, परसराम, शंकर, पूरन सिंह, चतुर सिंह, पूरन लाल मालवीय, टुकड़ों जावलकर, सुखराम पवार, शिवदयाल चौकीकर, रामदास पंडाग्रे आदि उपस्थित रहे।

ବିସ୍କୁଟ ସପ୍ଲାଇ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବିସ୍କୁଟ

ସମଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

କୋଇଲା ଖଣି ପେନ୍‌ସନଭୋଗୀ ସଂଘର ଧାରଣା

ତାଳଚେର,୧୦।୧୦(ନିପ୍ର): ସାଉଥବଳଣ୍ଡାସ୍ଥିତ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (ସିଏମ୍‌ପିଏଫ୍) ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ତାଳଚେର କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଛଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କୋଇଲା ଖଣି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପେନସନ ଯୋଜନାର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ପେନସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାନତା ଆଣିବା, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତି ତିନିବର୍ଷରେ ସେସ୍ ବୃଦ୍ଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ୨୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଟନ୍ ପିଛା ସେସ୍‌ର ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା, ପ୍ରତି ତିନିବର୍ଷରେ ପେନସନ ସମୀକ୍ଷା ଓ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ୧୯୯୮ର ଅଧିନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରାଯିବା, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ତରରେ ପେନସନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସରଳୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ପ୍ରଭୃତି ଛଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପେନ୍‌ସନଭୋଗୀ ସଂଘର ସଂଯୋଜକ ପିକେ ସିଂ ରାଠୋର, ସମ୍ପାଦକ କୁଞ୍ଜବନ ସାହୁ, ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ନିର୍ମଳଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତ୍ରିପୁର ଦେହୁରୀ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମର୍ମରେ ସିଏମ୍‌ପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

सरकारी नीति के अनुसार न्यूनतम पेंशन की उठी मांग

कोल इंडिया के कोल भविष्य निधि कार्यालय में प्रदर्शन करते लोग ● जागरण

जासं, देवघर: अखिल भारतीय कोयला पेंशन भोगी संघ के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीएमपीएफ आफिस कैंपस में धरना दिया गया। जिसमें देवघर के अलावा धनबाद, बोकारो, राजमहल के सदस्यों ने भी भाग लिया। मुख्य मांग पत्र पर चर्चा की गई। जिसमें सभी सरकारी और निजी कोयला कंपनियों से हर तीन साल में सेस बढ़ाने के प्रविधानों के साथ 20 रुपया प्रति टन के सेस के अनिवार्य संग्रह की प्रक्रिया तेज हो। हर तीन साल में पेंशन की समीक्षा। सरकारी नीति के तहत पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित किया जाए समेत अन्य मांग पत्र पर आवाज उठाई गई। नारे भी लगाए गए। धरना के अंतिम चरण में चार सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल क्षेत्रीय आयुक्त देवघर को मांग का ज्ञापन सौंपा। उसके बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में धरना कार्यक्रम को समाप्त किया गया। प्रतिनिधि मंडल में पीके सिंह, एसपी मिश्रा, एसएन तिवारी एवं एसबीपी बरनवाल शामिल हुए।

DAINIK JAGRAN 11-10-22

कोल इंडिया पेंशनर्स एसो. ने दिया धरना

जासं, आसनसोल : आल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को आसनसोल के उषाग्राम स्थित सीएमपीएफ कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इसके दौरान सीएमपीएफ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन के पदाधिकारी उमेश कुमार सिंह ने कहा कि कोयला उद्योग के पेंशनरों की काफी समस्याएं है। वर्षों से इसके समाधान की मांग की जा रही है। कोयला खान पेंशन योजना पुनर्गठन के लिए लोक लेखा समिति की 12वीं रिपोर्ट में संसद में जो सुझाव दिए गए हैं, उसे जल्द लागू किया जाए। सरकारी और निजी कोल कंपनियों से कोयला उत्पादन में प्रति टन 20 रुपये सेस लगाने तथा हर तीन साल में वृद्धि को लागू किया जाए। हर तीन साल में पेंशन की समीक्षा और संशोधन के लिए सीएमपीएस 1998 के प्रावधानों को लागू किया जाए। सम्मानजनक पेंशन के लिए न्यूनतम पेंशन राशि निर्धारित करें। विधवा या विधुर पेंशन की प्रक्रिया सरल करने की मांग वर्षों से लंबित है।

PRABHAT KHABAR

कोल पेंशनर्स एसोसिएशन ने क्षेत्रीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

सीएमपीएफ कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते एसोसिएशन के सदस्य.

आसनसोल. ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन, आसनसोल शाखा की ओर से पेंशन रिवीजन सहित विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को उषा ग्राम स्थित सीएमपीएफ कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया तथा क्षेत्रीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया. मौके पर ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन, आसनसोल शाखा के महासचिव पवन कुमार टंडन, अध्यक्ष डॉ एनजी मुखर्जी, विजन चक्रवर्ती, अनिल मल्होत्रा, केबी सिंह, एके उपाध्याय, संजय कुमार, उमेश कुमार सिंह, शिव बली सिंह सहित अन्य मौजद रहे. अध्यक्ष एनजी मुखर्जी ने बताया कि सुबह 10:00 बजे से दोपहर एक बजे तक सीएमपीएफ कमिश्नर दफ्तर के सामने धरना देने के उपरांत एक ज्ञापन सौंपा गया. महासचिव श्री टंडन ने बताया कि वर्ष 1998 में पेंशन स्कीम बनी और लागू हुई. उसमें प्रावधान था कि प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर पेंशन में रिवीजन होगा. लेकिन पिछले 25 साल से यह लंबित है. कोल इंडिया में लगभग एक लाख पेंशन धारकों को एक हजार से कम राशि मिलती है. पेंशन वृद्धि और विधवा पेंशन के सरलीकरण करने की मांग की गयी है. क्षेत्रीय आयुक्त ने इसे धनबाद कार्यालय में प्रेषित करने का आश्वासन दिया है.

10/10/22

देवघर. अखिल भारतीय कोयला पेंशनभोगी संघ के तत्वावधान में कोल पेंशनर्स कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया. इसमें संघ के दर्जनों सदस्यों ने अपनी भागीदारी दिखायी. संघ के संयोजक पीके सिंह राठौर ने कहा कि कोल पेंशनरों की समस्याओं पर विभाग ने कभी सार्थक पहल नहीं की. इससे संघ के पदाधिकारियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. संघ की ओर से छह सूत्री मांगों का ज्ञापन सीएमपीएफओ धनबाद के आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त देवघर को भेजा गया. संघ की मांगों में कोयला खान पेंशन योजना के पुनर्गठन के लिए लोक लेखा समिति की 12 वीं रिपोर्ट को त्वरित लागू करने, हर तीन साल में पेंशन की समीक्षा और संशोधन के लिए बने प्रावधानों का अनुपालन करने, सरकारी नीति के अनुसार पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने, -बैंक स्तर पर विधवा या विधुर पेंशन आरंभ की प्रक्रिया सरल की जाये आदि मांगें रखी गयी.

क्षेत्रीय आयुक्त कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय पर दिया

मध्यप्रदेश मिरर » बैतूल

madhyapradeshmirror@gmail.com

कोल माइंस पेंशनर एसोसिएशन एचएमएस के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार सहायक कमिश्नर को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष दिनकर साहू ने बताया कि सीएजी, पीएसी सुझावों पर सुस्त कार्रवाई और पेंशन पुनरीक्षण, वृद्धि ना होने के विरोध में एचएमएस के प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्रीय आयुक्त कोयला खान भविष्य निधि छिंदवाड़ा कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। इसके बाद सहायक कमिश्नर को छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आयुक्त धनबाद नई दिल्ली कोयला मंत्री के नाम सौंपा गया।

ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष डीके साहू, महामंत्री दयाराम झरबडे, उपाध्याय अजय सिंह राजपूत, मानिकराव कापसे कोषाध्यक्ष नागौराव वागद्रे, मुलताई शाखा से अध्यक्ष बीआर गवाड़े, सचिव उमराव, महासचिव अशोक सेलकरी, नारायण मिश्रा, विजय वर्मा, रामदास पंडाग्रे, इंदल पारधे, रामाशंकर, बाजीराव इंगवे, कुंदन लाल चौधरी, प्रेम लाल पंवार, परसराम उपस्थित रहे।

మంగళవారం, 11 అక్టోబర్ 2022

దేశవ్యాప్తంగా సీఎంపీఎఫ్ ఆఫీసుల ఎదుట పెన్షనర్ల ధర్నా

గోదావరివాణి విలేఖరి, కొత్తగూడెం, అక్టోబర్ 10: బొగ్గు పరిశ్రమల్లో పనిచేసి రిటైర్ అయిన విశ్రాంత కార్మికుల కు కోల్ మైన్స్ పెన్షన్ స్కీమ్ 1998 చట్టం ప్రకారం పెన్షన్ పెంపుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న సి.ఎం.పి.ఎఫ్. ఆఫీసుల ముందు విశ్రాంత కార్మికుల, ఉద్యోగులకు సంబంధించిన అసోసియేషన్ ల ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించి డిమాండ్ల తో కూడిన వినతి పత్రాలను సి.ఎం.పి.ఎఫ్ అధికారులకు ఇవ్వడం జరిగిందని ఆల్ ఇండియా కోల్ పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ కన్వీనర్ పి.కే. సింగ్ రాథోడ్ ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపారు, ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బొగ్గు పెన్షనర్లందరూ సీఎం పిఎస్ 1998 కింద పెన్షన్ పెంపుదల కోసం ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి సవరణ చేయాల్సి ఉండగా ఇంతవరకు సి.ఎం.పి.ఎఫ్.ట్రస్ట్ బోర్డు గాని కేంద్ర ప్రభుత్వం గాని సవరించలేదని ఆయన తెలిపారు. 1998 నుండి నేటి వరకు విశ్రాంత ఉద్యోగులకు, కార్మికుల కు పెన్షన్ సవరణ జరుగలేదని దీని వల్ల చాలా మంది విశ్రాంత ఉద్యోగులు, కార్మికులు తమ కుటుంబ పోషణకు తక్కువ పెన్షన్ తో అనేక అవస్తలు పడుతున్నారని ఆయన అన్నారు. విశ్రాంత ఉద్యోగులు, కార్మికులు గొంతెమ్మ కోరికలు కోరడం లేదని, న్యాయంగా, చట్ట ప్రకారం రావాల్సిన పెన్షన్ పెంపుదల కోసం,సౌకర్యాల కోసం ఆందోళన కార్యక్రమాలు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వివిధ రూపాల్లో చేయడం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. విశ్రాంత ఉద్యోగులు, కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం లో వారి ఓట్లతో గెలిచిన ఎమ్మెల్యే లు, ఎం.పి. లతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు సి.ఎం.పి.ఎఫ్ ట్రస్ట్ బోర్డు పట్టించుకోవడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. విశ్రాంత ఉద్యోగులు, కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని సి.ఎం.పి.ఎఫ్ ప్రాంతీయ కార్యాలయాల ముందు నేడు ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ధర్నా నిర్వహించి డిమాండ్ లతో కూడిన వినతి పత్రాలను సంబంధించిన సిఎంపిఎఫ్ ఆఫీసు అధికారులకు ఇవ్వడం జరిగిందని ఆయన అన్నారు ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం, సి.ఎం.పి.ఎఫ్. అధికారులు స్పందించి విశ్రాంత కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆయన కోరారు.

8 గోదావరి వాణి

సీఎంపీఎఫ్ ఆఫీస్ ఎదుట సింగరేణి రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల, కార్మికుల ధర్నా

గోదావరివాణి విలేఖరి, గోదావరిఖని, అక్టోబర్ 10: బొగ్గు గని విశ్రాంత ఉద్యోగులకు, కార్మికులకు పెన్షన్ పెంపుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం గోదావరిఖని ఐ.బి. కాలనీలో ఉన్న సిఎంపిఎఫ్ ఆఫీసు ముందు ధర్నా నిర్వహించారు. డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని సెక్షన్ ఆఫీసర్ రమేష్‌కుమార్‌కు అందజేసినట్లు సింగరేణి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయిస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు దండంరాజు రాంచందర్ రావు, ఉపాధ్యక్షులు ఆళవందార్ వేణుమాధవ్ పేర్కొన్నారు. కొన్ని 24 సంవత్సరాలుగా విశ్రాంత కార్మికుల కు పెన్షన్ పెంపుదల జరుగలేదని, దీని వల్ల చాలా మంది ఈ పెన్షన్ పై ఆధారపడ్డ కుటుంబాలు పోషణకు అనేక అవస్థలు పడుతున్నారని వారు పేర్కొన్నారు. సిఎంపిఎఫ్ అధికారులు స్పందించి విశ్రాంత ఉద్యోగులు, కార్మికులకు వెంటనే పెన్షన్ పెంపుదల కోసం సంబంధిత ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారం కోసం కృషి చేయాలని వారు కోరారు. పింఛనుదారుల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇలా ఉన్నాయి. బొగ్గు గనుల పెన్షన్ స్కీమ్ పునర్నిర్మాణం కోసం పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ యొక్క 12వ నివేదికలో ఉన్న సూచనలపై సత్వర అమలు (మార్చి 18, 2020న పార్లమెంటులో సమర్పించబడింది) 2. పదవీ విరమణ తేదీతో సంబంధం లేకుండా ఏకరీతి పెన్షన్‌ను నిర్ధారించడానికి పెన్షన్‌లో భాగంగా డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ (DR) భాగాన్ని చేర్చండి 3. అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ బొగ్గు కంపెనీల నుండి ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి సెస్‌ను పెంచే నిబంధనలతో టన్నుకు రూ. 20 చొప్పున తప్పనిసరిగా వసూలు చేసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయండి. 4. ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పెన్షన్ను సమీక్షించడానికి సవరించడానికి సీఎంపిఎస్, ఎస్-1998లో రూపొందించిన నిబంధనలను అనుసరించండి 5. ప్రభుత్వ విధానం ప్రకారం పెన్షనర్‌కు కనీస పెన్షన్ ఉండేలా చూసుకోండి. 6. బ్యాంకు స్థాయిలో వితంతువు/వితంతువు పెన్షన్‌ను మళ్లీ మళ్లీ ప్రారంభించే సాధారణ ప్రక్రియను ప్రకటించే బదులు, ప్రక్రియను నిజమైన అర్థంలో ప్రారంభించనివ్వండి. తదితర డిమాండ్లతో కూడిన పత్రాన్ని అందజేశారు.

ఆంధ్రప్రభ

రామగుండం / మంథని నియోజకవర్గం 11

సింగరేణి విశ్రాంత ఉద్యోగుల ఉద్యమం ఉధృతం

- పెన్షన్ పెంపుదల కోసం యాజమాన్యానికి డిమాండ్

గోదావరిఖని, అక్టోబర్ 10 (ప్రభన్యూస్) : బొగ్గు గని విశ్రాంత ఉద్యోగులకు, కార్మికులకు పెన్షన్ పెంపుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం గోదావరిఖని ఐబీకాలనీలో ఉన్న సిఎంపిఎఫ్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని సెక్షన్ ఆఫీసర్ రమేష్‌కుమార్‌కు అందించామని సింగరేణి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయిస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు దండంరాజు రాంచందర్ రావు, ఉపాధ్యక్షులు ఆళవందార్ వేణు మాధవ్‌లు పేర్కొన్నారు. గత కొన్ని 24 సంవత్సరాలుగా విశ్రాంత కార్మికుల కు పెన్షన్ పెంపుదల జరుగలేదని, దీని వల్ల చాలా మంది ఈ పెన్షన్ పై ఆధారపడ్డ కుటుంబాలు పోషణకు అనేక అవస్తలు పడుతున్నారన్నారు. సిఎంపిఎఫ్ అధికారులు స్పందించి విశ్రాంత ఉద్యోగులు, కార్మికులకు వెంటనే పెన్షన్ పెంపుదలకోసం సంబంధిత ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారం కోసం కృషి చేయాలని కోరారు.

ధర్నా నిర్వహిస్తున్న సింగరేణి విశ్రాంత కార్మికులు

Date: 11/10/2022, Edition: Karimnagar, Page: 5
Source : https://epaper.prabhanews.com/

వార్త

విశ్రాంత బొగ్గు కార్మికుల జీవితాల్లో వెలుగునింపెదెవరు?

ఆళవందార్ వేణు మాధవ్

బాహ్య ప్రపంచానికి సంబంధం లేకుండా బొగ్గుపొరల్లోకి చొచ్చుకొని వెళ్లి ప్రకృతికి విరుద్ధంగా రాత్రనక, పగలనక కష్టపడి అటుసంస్థకు లాభాలు ఆర్జించేందుకు, ఇటు ప్రపంచానికి వెలుగు నింపేందుకు కృషి చేసిన సింగరేణి కార్మికుని బాధలు ఎన్నో ఉన్నాయి. పనిచేసిన కాలంలో యాజమాన్యం ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాలు, బహుమతులు, బోనస్, ఉచిత నివాసం, ఉచిత కరెంట్, గ్యాస్ లాంటివి అనుభవించడంలో కార్మికుల పోరాటాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆనాడు గొప్ప జీతాలతో అనుభవించిన బొగ్గువిశ్రాంత కార్మికుల జీవితాల్లో చీకట్లు ముసురుకొని ఉన్నాయి. నేటి ధరలకు అనుగుణంగా పెన్షన్ పెరగకపోవడంతో ఎంతోమంది తీవ్ర అగచాట్లకు గురికావడం జరుగుతుంది. 1998లో ప్రవేశపెట్టిన కోల్‌మైన్స్ పెన్షన్ స్కీం ప్రకారం కార్మికుడు దిగిపోయిన చివరి నెలలోని బేసిక్, కరవుభత్యంలో 25 శాతంను పెన్షన్‌గా నిర్ణయిస్తారు. ఇట్టి పెన్షన్ నిధిని కేంద్రబొగ్గు మంత్రిత్వశాఖ ఆధీనంలో ఉన్న కోల్‌మైన్స్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ట్రస్ట్ సభ్యులు పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటారు. ఈ ట్రస్ట్‌బోర్డులో కార్మిక సంఘ ప్రతినిధులు కూడా ఉంటారు. 24 సంవత్సరాల క్రితం దిగిపోయిన కార్మికులకు వారి వేతనాలను బట్టి నిర్ణయించిన కనీసం పెన్షన్ 350 రూపాయలను ఇంతవరకు పెంచకపోవడం అమానుషం. ఇప్పటికీ మూడు వందలు, ఐదువందల రూపాయల పెన్షన్ తీసుకునేవారు ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రప్రభుత్వం చెల్లించే వృద్ధాప్య పెన్షన్2,016 రూపాయల కన్నా తక్కువ పెన్షన్ లభించడం ఆశ్చర్యకరం. బొగ్గుపెన్షన్ తీసుకునేవారు ఆసరా పెన్షన్‌కు అర్హులుకారు. చాలా మంది దిగిపోయిన కార్మికులు వారి వారసులు, కుటుంబ సభ్యులు ఆలనా,పాలన సరిగా లేకపోవడం, కొంత మంది సెక్యూరిటీ గార్డులుగా, పండ్లు, కూరగాయల అమ్ముకుంటూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. సర్వీస్‌లో ఉన్నప్పుడు దర్జాగా బతికిన వీరిని చూస్తే జాలి కలగకమానదు. పదవీ విరమణ పొందినప్పుడు లభించిన ప్రావిడెంట్ ఫండ్ గ్రాట్యూటీ సొమ్మును పిల్లల చదువులకు,వివాహాలకు హారతికర్పూరంలాగా కరిగిపోయాయి, కరిగిపోతున్నాయి. చేతిలో చిల్లిగవ్వలేకుండా కాలం వెళ్లబుచ్చుతున్నారు. చాలీచాలని పెన్షన్‌తోపాటు అధిక వయోభారం వల్ల జబ్బులకు యాజమాన్యం జారీ చేసిన మెడికల్ కార్డ్ ద్వారా లభించే ఎనిమిది లక్షల రూపాయల బీమా నేటి వైద్య ఖర్చులకు ఏమాత్రం సరిపోవు. సింగరేణి ఏరియా ఆస్పత్రికి వెళ్లితే అక్కడ కూడా విశ్రాంత ఉద్యోగుల త్యాగాలను మరిచి వారివద్ద నుండి వైద్యఖర్చులు వసూలు చేయడం కడు శోచనీయం. కనీసం పెన్షన్ పెంచాలని, నేటి ధరలకు అనుగుణంగా కరవు భత్యంతో కూడిన పెన్షన్ పెంచాలని కోల్‌మైన్స్ పెన్షన్ స్కీం 1998 ప్రకారం ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి సమీక్షించి పెన్షన్ నిబంధనలను బొగ్గు సంస్థ యాజమాన్యాలు మరవడం బాధాకరం. చీకటి సూర్యులుగా జీవించిన వీరి జీవితాల్లో వెలుగు నింపేదెవరు? ●

Date: 11/10/2022, Edition: karimnagar(karimnagar Main), Page: 4
Source : https://epaper.vaartha.com/

సీఎంపిఎఫ్ ఆఫీసుల ముందు పెన్షనర్ల ధర్నా

విశాలాంధ్ర ప్రతినిధి–పెద్దపల్లి,సింగరేణి: బొగ్గు గని విశ్రాంత ఉద్యోగులకు, కార్మికుల కు పెన్షన్ పెంపుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం గోదావరిఖని సిఎంపిఎఫ్ ఆఫీసు ముందు ధర్నా నిర్వహించి, డిమాండ్ల తో కూడిన వినతి పత్రాన్ని సెక్షన్ ఆఫీసర్ రమేష్ కుమార్ కు ఇవ్వడం జరిగిందని సింగరేణి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయిస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు దండంరాజు రాంచందర్ రావు, ఉపాధ్యక్షులు ఆళవందార్ వేణు మాధవ్ లు తెలిపారు. 24 సంవత్సరాలుగా విశ్రాంత కార్మికుల కు పెన్షన్ పెంపుదల జరుగలేదని, దీని వల్ల చాలా మంది ఈ పెన్షన్ పై ఆధారపడ్డ కుటుంబాలు పోషణకు అనేక అవస్తలు పడుతున్నారని వారు వివరించారు. సిఎంపిఎఫ్ అధికారులు స్పందించి విశ్రాంత ఉద్యోగులు, కార్మికులు కు వెంటనే పెన్షన్ పెంపుదల కోసం సంబంధిత ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారం కోసం కృషి చేయాలని వారు కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో సింగరేణి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయిస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ హైదరాబాద్ నాయకులు నూనె రాజేశం,మారనేని లచ్చన్న,ఉత్తూరు రాజన్న,నర్సయ్య, గౌరవెల్లి రాంచం దర్ రావు,దిడ్డి రమేష్ తో పాటు సింగరేణి విశ్రాంత కార్మికులు పాల్గొన్నారు.

CMPF ఆఫీస్ ముట్టడి

- రిటైర్డ్ కార్మికుల పింఛన్లు పెంచాలని సింగరేణి రిటైర్డ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ డిమాండ్
- మద్దతు తెలిపిన రామగుండం తీన్మార్ మల్లన్న టీమ్
- డిమాండ్లను నెరవేర్చాలి : అంబటి నరేష్

శనార్తి తెలంగాణ, పెద్దపల్లి : సింగరేణి విశ్రాంత కార్మికుల పింఛన్లు పెంచాలని కోరుతూ సోమవారం గోదావరిఖని లోని cmpf ఆఫీస్ ను ముట్టడించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రామగుండం తీన్మార్ మల్లన్న టీమ్ కన్వీనర్ అంబటి నరేష్ మద్దతు తెలిపారు. ధర్నాలో పాల్గొన్న అనంతరం సింగరేణి రిటైర్డ్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ వేణుమాధవ్ మాట్లాడుతూ సింగరేణి బొగ్గు సంస్థలో దాదాపు 30, 40 సం॥లు అహర్నిశలు కష్టపడి సంస్థను కాపాడటంలో విశ్రాంత ఉద్యోగుల శ్రమించారని గుర్తు చేశారు. 1993 సం॥లో సింగరేణి సంస్థ నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మరల లాభాల లోకి తేవడంలో మా వంతు కృషి చేశామన్నారు. మా త్యాగాలు గుర్తించి.. కోల్ మైన్స్ పెన్షన్ స్కీం-1998 సవరణ చేసి, కనీస పింఛన్ రూ.15000 వేలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. పింఛన్ పథకంలో పేర్కొన నిబంధన ప్రకారం ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి కరువు భత్యంతో కూడిన పింఛన్ చెల్లించాలన్నారు. కాంట్రిబ్యుటరీ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ మెడికల్ స్కీం (సిపిఆర్ఎమ్ఎస్ఎ) కార్డుల వైద్య ఖర్చుల పరిమితి 8 లక్షల బదులుగా అపరిమితంగా చెల్లించాలన్నారు. ఇల్లు లేని విశ్రాంత ఉద్యోగులకు హైదరా

బాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని కోరారు. బీబీ నగర్ లోని ఎయిమ్స్ హాస్పటల్ నందు వైద్య సౌకర్యాం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. డిసెంబర్ 23న " సింగరేణి డే" ఉత్సవాలను హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తూ విశ్రాంత ఉద్యోగులను ఆహ్వానించాలని.. సింగరేణి విశ్రాంత ఉద్యోగులకు పిపిఓ తో కూడిన ప్రత్యేక గుర్తుంపు కార్డులు జారీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

సీఎంపీఎఫ్ కార్యాలయం ఎదుట పెన్షనర్ల ధర్నా

సూర్య-గోదావరిఖని: పట్టణంలోని సి.ఎం.పి.ఎఫ్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం ఎదుట సోమవారం బొగ్గు పరిశ్రమలకు చెందిన విశ్రాంత ఉద్యోగులు, కార్మికులు ధర్నా చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా బొగ్గు పరిశ్రమల్లో పనిచేసిన విశ్రాంత ఉద్యోగులకు, కార్మికుల కు పెన్షన్ పెంపుదల చేయాలనే ప్రధాన డిమాండ్ తో పాటు ఇతర డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని సెక్షన్ ఆఫీసర్ రమేష్ కుమార్ కు అందజేశారు. అనంతరం సింగరేణి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయిస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు దండంరాజు రాంచందర్ రావు, ఉపాధ్యక్షులు ఆళవందార్ వేణు మాధవ్ మాట్లాడుతూ గత 24 సంవత్సరాలుగా విశ్రాంత కార్మికుల కు పెన్షన్ పెంపుదల జరుగలేదని, దీంతో పెన్షన్ పై ఆధారపడ్డ కుటుంబాలు పోషణకు అనేక అవస్తలు పడుతున్నారని ఆవేదన చెందారు. ఇప్పటికైనా సిఎంపిఎఫ్ అధికారులు స్పందించి విశ్రాంత ఉద్యోగులు, కార్మికులు వెంటనే పెన్షన్ పెంపుదల కోసం సంబంధిత ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి తమ డిమాండ్ల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని వారు కోరారు. బొగ్గు గనుల పెన్షన్ స్కీమ్ పునర్నిర్మాణం కోసం పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ యొక్క 12వ నివేదికలో ఉన్న సూచనలు సత్వర అమలు, పదవీ విరమణ తేదీతో సంబంధం లేకుండా ఏకరీతి పెన్షన్‌ను నిర్ధారించడానికి పెన్షన్‌లో భాగంగా డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ భాగాన్ని చేర్చాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బొగ్గు కంపెనీల నుండి ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి సెస్‌ను పెంచే నిబంధనలతో టన్నుకు రూ.20 చొప్పున తప్పనిసరిగా వసూలు చేసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని, ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పెన్షన్‌ను సమీక్షించడానికి, సవరించడానికి కోల్ మైన్స్ పెన్షన్ స్కీమ్ చట్టం 1998లో రూపొందించిన నిబంధనలను అమలు చేయాలని కోరారు. అలాగే ప్రభుత్వ విధానం ప్రకారం పెన్షనర్‌కు కనీస పెన్షన్ ఉండేలా అమలు చేయాలని, బ్యాంకు స్థాయిలో వితంతువు పెన్షన్‌కు సంబంధించిన ఇబ్బందులను తొలగించాలని కోరారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో సింగరేణి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయిస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ హైదరాబాద్ నాయకులు నూనె రాజేశం, మారనేని లచ్చన్న, ఉత్తూరు రాజన్న, నర్సయ్య, గౌరవెల్లి రాంచందర్ రావు, దిడ్డి రమేష్ తో పాటు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, కార్మికులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు పాల్గొన్నారు.

మాట్లాడుతున్న సింగరేణి విశ్రాంత కార్మికుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు గజెల్లి వెంకటయ్య

10న విశ్రాంత కార్మికుల ధర్నా

మంచిర్యాల పట్టణం: సింగరేణి విశ్రాంత కార్మికులకు కోల్ మైన్స్ పెన్షన్ పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నెల 10న గోదావరిఖనిలోని సీఎంపీఎఫ్ కార్యాలయం ఎదుట నిర్వహించే ధర్నాను విజయవంతం చేయాలని ఆ సంఘం అధ్యక్షుడు గజెల్లి వెంకటయ్య కోరారు. మంచిర్యాలలో శనివారం ఆయన మాట్లాడుతూ.. 1989లో చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి పెన్షన్ పెంచాలని ఆదేశాలు ఉన్నా.. 24 ఏళ్ల నుంచి పెంచడంలేదని ఆరోపించారు. ఆ సంఘం నాయకులు వెంకటేశం, చంద్రయ్య, జ్ఞాని. లక్ష్మనారాయణ గౌడ్, అంజన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు.

సీఎంపీఎఫ్ కార్యాలయం ఎదుట విశ్రాంత కార్మికుల ధర్నా

ధర్నా చేస్తున్న విశ్రాంత కార్మికులు

గోదావరిఖని, న్యూస్‌టుడే : విశ్రాంత బొగ్గు గని కార్మికుల పింఛను సవరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ గోదావరిఖని సీఎంపీఎఫ్ కార్యాలయం ఎదుట విశ్రాంత కార్మికులు సోమవారం ధర్నా చేపట్టారు. మూడేళ్లకోసారి సవరించాల్సి ఉండగా 1998 సంవత్సరం నుంచి సవరించలేదని వెల్లడించారు. కనీస పింఛను నిర్ణయించాలని నినాదాలు చేశారు. ఓ వైపు వర్షం వస్తున్నా విశ్రాంత కార్మికులు సీఎంపీఎఫ్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేపట్టారు. అఖిల భారత బొగ్గుగని పింఛనుదారుల సంఘం పిలుపు మేరకు చేపట్టిన ధర్నాలో నాయకులు పి.టి.స్వామి, ఎం.బాబురావు, వెంకటేశం, రాజేశం పాల్గొన్నారు.

Telangana Today E-PAPER
Monday, July 18, 2022
Price Rs. 6
TELANGANA EDITION
Vol. 6 • No. 215 • Pages 12
05 | Telangana Today News from STATE

Coal pensioners for review of CMPS-98

CITY BUREAU
Hyderabad

The All India Coal Pensioners' Association urged Prime Minister Narendra Modi to constitute a high-power committee on the issue of review and revision under Coal Mines Pension Scheme (CMPS) -1998 while including its representatives.

The association, in a letter to the Prime Minister, sought to reiterate that pension can be increased without any budgetary support from the Central government and meeting the same from the coal production companies by levying a small amount on the selling price on account of pension fund as being done by some of the electricity producing and distribution companies.

Seeking revision and increase in the pension of the coal pensioners, the coal pensioners from across the country have decided to stage a relay dharna at Jantar Mantar, New Delhi from July 25.

The association pointed out that the contributory pension scheme CMPS-1998 was introduced for retired employees in coal sector by NDA government in 1998. It was claimed as a revolutionary measure by the government for providing robust social security to employees and workers.

However, the retired employees of Coal India, SCCL and some other private companies have been striving for to bring the issues to the notice of the competent departments. Many coal pensioners/their widows are getting less than Rs 500 to Rs 1,000 as pension, whereas, under government schemes for older people, the amount is more than this, it said.

https://psuwatch.com/coal-pensioners-start-1-month-long-dharna-at-jantar-mantar-to-demand-revision/

Tuesday, July 26, 2022

PSUWATCH
Fast | Accurate | Engaging

Coal pensioners start 1-month-long dharna at Jantar Mantar to demand revision

*By**PSU Watch Bureau***

July 25, 2022

Over 50,000 coal pensioners are receiving a pension of less than Rs 1,000 per month, said the AICPA & AIACE as they started a one-month long dharna to demand revision

Coal pensioners start 1-month-long dharna at Jantar Mantar to demand revision

- **Coal pensioners from across the country have gathered at Jantar Mantar from today and participated in relay dharna which will end by 31st August**
- **The amount fixed on the date of retirement of coal pensioners remains same till date since its implementation in 1998, even after 24 years**

New Delhi: More than 50,000 pensioners who retired from state-run coal PSUs are receiving a pension of less than Rs 1,000 per month, said the All Indian Coal Pensioners Association (AICPA) & All India Association of Coal Executives (AIACE) in a statement on Monday as they started a one-month long dharna to protest demand pension revision for coal pensioners. "All Indian Coal Pensioners Association (AICPA) & All India Association of Coal Executives (AIACE), in association with other coal miners pensioners and welfare

organisations, have started one month long dharna wef 25/7/2022 at Jantar Mantar, New Delhi, for review of CMPS 1998 and revision of pension for coal miners thereof."

"Coal pensioners from across the country — like Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Chhatisgarh, Jharkhand, Bihar, Odisha, West Bengal, Uttar Pardesh, Delhi and other states — have gathered at Jantar Mantar from today and participated in relay dharna which will end by 31st August, 22," said the associations.

50,000 coal pensioners receiving less than Rs 1,000 per month

After the nationalisation of the coal industry in 1973, employees in coal PSUs got the benefit of a pension scheme in 1998. The scheme covered pensioners from Coal India Ltd (CIL), Singareni Collieries Company Ltd (SCCL) and few other coal companies. Under CMPS-1998, the Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO), working under the Ministry of Coal, was entrusted with this task. A pension fund was created by equal contributions from emplyees and employer. There was a provision to review after every three years but it was never done regularly, coal pensioners' associations said. "The review and revision has not been done for the last 24 years and more than 50,000 pensioners are getting less than Rs 1,000 per month, which is quite insufficient to meet daily needs," they added.

"This lack of review has caused mismanagement of the fund. The scheme also failed to take into consideration the scenario where contribution from employees reduced due to the introduction of high yield mechanisation and slowly reduction of manpower from about 7 lakh (at the time of the implementation of the scheme) to about 3.5 lakh as of now," said the associations.

The amount fixed on the date of retirement of coal pensioners remains same till date since its implementation in 1998, even after 24 years.

Coal pensioners demand upward revision of pension

"The coal pensioners desire and demand upward revision of pension at the earliest. Moreover, an employee in the same grade but retiring at a later date enjoys higher pension compared to an equally ranked employee retiring earlier. We also want this issue to be resolved by implementing ONE RANK – ONE PENSION rule," said the statement.

"For the resolution of our grievances, so far we have approached 89 Member of Parliaments, including the Hon'ble Prime Minister, Coal Minister and others. And 48 Members of Parliament have written recommendation letters to the Coal Minister. In spite of all these efforts, there is no ray of any hope towards solving the misery of pensioners in the coal sector," said the statement.

"It is a bitter truth that, past decisions and present indecisions, have made enhancement of pension a nightmare and a distant dream for pensioners leading to the demise of many

elderly pensioners every year. In view of these stated facts, to draw the attention of the government and its various agencies, we are on a spree of relay Dharna at Jantar Mantar from 25th July, 2022 and intend to extend it up to 31st August, so that the revision and enhancement of pension of we pensioners can be hastened without any further delay," said the associations.

(***PSU Watch***– *India's Business News centre that places the spotlight on PSUs, Bureaucracy, Defence and Public Policy is now on Google News. Click* ***here*** *to follow. Also,* ***join PSU Watch Channel*** *in your Telegram. You may also follow*

दैनिक भास्कर धनबाद, रविवार 07 अगस्त, 2022 | 02

बकाए इंटरेस्ट राशि की भुगतान के लिए कोल इंडिया चेयरमैन को पत्र

धनबाद | सेवानिवृत्त कोल अधिकारियों के बकाए इंटरेस्ट की राशि की भुगतान के लिए आल इंडिया एसोसिएशन आफ कोल एक्जीटिव के प्रधान महासचिव पीके सिंह राठौर ने कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को पत्र लिखा है। चेयरमैन को लिखे पत्र में राठौर ने कहा है कि कोयला मंत्रालय से जनवरी 2022 में आदेश आने के बावजूद अब तक इंटरेस्ट राशि का भुगतान नहीं होना चिंता का विषय है। एक जनवरी 2007 से एनपीएस लागू होने के बाद से कोल एक्जीटिव का पैसा 12 साल तक अपने पास रखी रही। इसे लेकर एसोसिएशन ने लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद कोयला मंत्रालय ने जनवरी 2022 में इंटरेस्ट की राशि की भुगतान का कोल इंडिया को आदेश दिया। लेकिन कोल इंडिया ने अब तक भुगतान नहीं किया।

दैनिक भास्कर नर्मदापुरम, सोमवार, 15 अगस्त, 2022 | 19

15 हजार रुपए मासिक पेंशन देने कोल पेंशनरों ने की मांग

भास्कर संवाददाता | बैतूल

कोल माइंस पेंशनर एसोसिएशन एचएमएस की मासिक बैठक रविवार को शहीद भवन में आयोजित की। जिला अध्यक्ष डीके साहू ने कहा कोल मंत्रालय भारत सरकार से वर्ष 1998 में जो 1 हजार की वैल्यूएशन थी, आज की तारीख में उस 1 हजार के वैल्यूएशन के बराबर मासिक पेंशन या 15 हजार मासिक पेंशन दिए जाने की मांग की है। इस दौरान निर्णय लिया कि भारत सरकार द्वारा पेंशनरों की मांगों को जल्द ही पूर्ण नहीं किया गया तो आगामी समय में ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन के संयोजक पीके सिंह राठौड़ के आह्वान पर 5 दिसंबर को नई दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। महामंत्री डीआर झरबड़े ने बताया संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अक्टूबर से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 1 नवंबर से सभी पेंशनरों को पेंशन फार्म जीवित प्रमाण पत्र माह के अंतिम तारीख तक अपने- अपने बैंक में जमा कराएं। बैठक में अध्यक्ष डीके साहू, महामंत्री डीआर झरबड़े, कोषाध्यक्ष नागोराव वागद्रे, उपा अजय सिंह राजपूत, मानिकराव कापसे, शिवदयाल चौकीकर, अशोक सेलकरी, नारायण मिश्रा, विजय वर्मा, रामदास पंडाग्रे, आरडी सोनी, रायमल वरवड़े, मिट्ठू लोखंडे, चतुर सिंह, तुलसीराम मासोदकर, मंगल मालवीय, पूरन लाल मालवीय सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।